प्रतिवेद्य

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 3832-3833/2020

(एसएलपी (सी) सं. 26669-26670/2018 से उत्पन्न)

मनोहर लाल जाट व अन्य आदि ... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य आदि ..... प्रतिवादी (गण)

के साथ

सिविल याचिका संख्या 3834/2020

(एसएलपी (सी) संख्या 26671/2018 से उत्पन्न)

निर्णय

एस. रवींद्र भट्ट, न्यायाधीश

1. अनुमति प्रदान की गई। सभी पक्षों के अधिवक्तओं की सहमति से, अपीलों पर अंतिम रूप से सुनवाई की गई और 24 जनवरी 2020 को निर्णय सुरक्षित रखा गया। ये अपीलें राजस्थान उच्च न्यायालय के

सामान्य फैसले को चुनौती देती हैं[1]। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने आक्षेपित निर्णय द्वारा उस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए एक आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि वर्तमान अपीलकर्ता (जिसे इसके पश्चात "प्रत्यक्ष भर्ती" या "डीआरएस " के रूप में संदर्भित किया गया है) प्रतिवादी के अतिरिक्त वरिष्ठता का दावा करने के हकदार नहीं थे, जिसे इसके बाद "विभागीय पदोन्नत" या "डीपीएस" कहा गया है। डीआरएस ने पहली बार उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि डीपीएस की वरिष्ठता सूची, पहले के पदों पर दिखाने वाली, असमर्थनीय थी, एकल न्यायाधीश ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया था। हालांकि, खण्ड पीठ ने अपीलकर्ताओं को भर्ती किए जाने वाले डीपीएस की पात्रता पर सवाल उठाने की अनुमति दे दी है।

2. प्रासंगिक तथ्य यह है कि 01.09.2009 को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने कर सहायकों के 531 पदों के सृजन के लिए अनुमोदन प्रदान किया। इस नवसृजित पद में 23 और पदों का इजाफा किया गया, जिन्हें कैडर में शामिल किया गया और कर सहायकों के ऐसे नवसृजित पदों की अंतिम संख्या 554 हो गई। राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवाएं सामान्य शाखा नियमावली, 1975 में संशोधन, दिनांक 01.12.2010 से प्रभावी, कर सहायकों के पदों को भरने की प्रक्रिया को

---

1 खंड पीठ विशेष अपील रिट संख्या 1053/2017 और खंड पीठ विशेष अपील रिट संख्या 1250/2017 में, जयपुर पीठ

निर्धारित करता है। संशोधन नियमों की अनुसूची-I में पदों को भरने के तरीके को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:

"100% सीधी भर्ती द्वारा:

(क) अनुसूची III के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 80%

(ख) 20% वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसचिवीय कर्मचारियों में से चयन द्वारा जो अनुसूची II के अनुसार विभागीय परीक्षा के माध्यम से"

3. 4 अक्तूबर, 2010 को दोनों श्रेणियों की भर्ती के लिए एक विभागीय चयन समिति का गठन किया गया था और कर सहायकों के सभी 554 पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र शुरू की गई थी। नियमों के अनुसार, सीधी भर्ती के 80% कोटे को 443 रिक्तियों की सीमा तक और 111 डीपीएस में से भरने का प्रस्ताव था। तदनुसार, 25.01.2011 को और डीआरएस की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। डीआरएस की भर्ती के लिए नियमों के तहत निर्धारित लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी; उसके बाद 15.05.2011 को टंकण परीक्षा आयोजित की गई। इस टंकण परीक्षा में 356 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 16.05.2011 को, डीआरएस के लिए आयोजित परीक्षा के अनंतिम परिणाम घोषित किए गए थे। तत्पश्चात वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त द्वारा सफल उम्मीदवारों की सूची पुलिस अधिकारियों को उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए संलग्न करते हुए स्पष्ट रूप से पत्र लिखे गए थे।

24.05.2011 को, विभाग ने डीपीएस के लिए 20% कोटा भरने के लिए विज्ञापन दिया। इससे पहले, 24.06.2011 को डीपी के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव था; हालाँकि, यह पहले 11.06.2011 और 12.06.2011 को आयोजित किया गया था। डीपीएस के लिए इन परीक्षणों के परिणाम 14.06.2011 को घोषित किए गए और विभाग ने 23.06.2011 को पदोन्नति पत्र जारी किए। 24.06.2011 को अपीलकर्ताओं को पुलिस सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के लिए पत्र जारी किए गए। हालांकि इस समय तक डीपीएस को पहले ही पदोन्नत कर दिया गया था, और उन्होंने अपने पदों का प्रभार ले लिया था। डीआरएस के नियुक्ति आदेश बाद में 04-07-2011 को जारी किए गए थे।

4. 5 जून, 2013 को, राजस्थान राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग ने एक वरिष्ठता सूची प्रकाशित की, जिसमें 20% कोटा में डीपीएस के रूप में नियुक्त लोगों को डीआर/अपीलकर्ताओं से वरिष्ठ के रूप में दिखाया गया था। स्पष्ट रूप से, कुछ डीआरएस - अपीलकर्ताओं सहित ने इस नियुक्ति पर आपत्ति जताई और वरिष्ठता सूची में सुधार की मांग की[2]। एक अन्य अनंतिम/अस्थायी वरिष्ठता सूची 15-05-2014 को जारी की गई थी, जिसमें स्थिति अलग नहीं थी क्योंकि डीपीएस को डीआरएस से

---

2 तीसरे अपीलकर्ता, अंकुर कुमार बंसल ने दिनांक 27.06.2013 के एक अभ्यावेदन के माध्यम से यह कहते हुए आपत्ति की कि डीपीएस को डीआरएस से ऊपर रखना अनुचित और नियमों के विपरीत था।

ऊपर दिखाया गया था। अपीलकर्ताओं ने फिर आपत्ति जताई; फिर भी 18-09-2015 को विभाग ने इसके द्वारा प्रकाशित अंतिम सूची में उनकी पिछली स्थिति की तथ्यात्मक पुष्टि की।

5. प्रत्यक्ष भर्तियाँ (डीआरएस) ने वरिष्ठता सूची को कानून के विपरीत बताते हुए रिट याचिकाओं[3] का एक समूह दायर किया। विभाग द्वारा 30.05.2016 को एक और वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, जिसमें डीपीएस की पिछली स्थिति को यथावत रखा गया था। यह एक अन्य कार्यवाही के समक्ष चुनौती का विषय बन गया[4]। हालांकि दो रिट कार्यवाहियों ने कुछ डीपीएस और आधिकारिक उत्तरदाताओं को छोड़कर डीआरएस को आवंटित वरिष्ठता स्थिति को चुनौती दी थी, किसी अन्य को पक्षकार नहीं बनाया गया था। रिट याचिका में आपत्ति के प्रमुख आधार यह थे कि डीआरएस और डीपीएस की भर्तियां एक साथ हुई थीं और विभागीय उम्मीदवारों को गलत तरीके से पहले नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे, बिना किसी कारण के यह सुनिश्चित करने के अलावा कि कर निरीक्षकों के संवर्ग में उनके प्रवेश की तारीखें पहले थीं, ताकि उनके आगे के कैरियर उन्नयन का पक्ष लिया जा सके।

6. उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक

---

3 मनोहर लाल जाट & अन्य बनाम राजस्थान राज्य & अन्य

4 गजेंद्र सिंह & अन्य बनाम राजस्थान राज्य & अन्य सीडब्ल्यूपी एनपी. 2017 का 4630

25.05.2017 के निर्णय द्वारा संबंधित नियमों के नियम 27 (इसके बाद "वरिष्ठता नियम" कहा गया है)[5] पर विचार किया।

7. एकल न्यायाधीश ने नियम 27(2) पर विशेष रूप से ध्यान दिया जिसमें कहा गया है कि जो लोग पहले के चयन मे भर्ती प्रक्रिया से गुजरते हैं उन्हें जो बाद की प्रक्रिया द्वारा चयन में भर्ती होते हैं से वरिष्ठ पदों पर रखा जाएगा। एकल न्यायाधीश ने इस प्रकार निष्कर्ष निकालाः

“16. नियम 2 (1) की एक झलक से पता चलेगा कि 25 जनवरी, 2011 को जारी विज्ञापन वर्ष 2010-2011 की रिक्तियों के संदर्भ में जारी किया गया था। जाहिर है, 24 मई, 2011 का विज्ञापन, बाद के वर्ष 2011-2012 की रिक्तियों के संदर्भ में एक भर्ती प्रक्रिया होगी प्रतिवादी अपने जवाबी हलफनामों के साथ-साथ दलीलों के दौरान इस पहलू पर आश्चर्यजनक रूप से मौन हैं।

17. 1975 के नियमों के नियम 2 (1) और 27 के संयुक्त पठन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि चयन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किए गए व्यक्ति, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण का विषय नहीं है, बाद के चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किए गए व्यक्तियों से वरिष्ठ रैंक पर होंगे। इस प्रकार, खंड 2(1) के साथ पठित नियम 27 के तहत “बाद में चयन प्रक्रिया” वाक्यांश इस

5राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975

तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि याचिकाकर्ता वे कर्मचारी हैं जिन्हें पिछले चयन में नियुक्त किया गया था और निजी प्रतिवादी (विभागीय कर्मचारी) वे व्यक्ति हैं जिन्हें "बाद में चयन प्रक्रिया" में नियुक्ति दी गई थी। इसलिए, उन विभागीय उम्मीदवारों को याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो पिछली चयन प्रक्रिया के सफल चयनित उम्मीदवार हैं।"

8. विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से असंतुष्ट डीआरएस ने 2017 की खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 1053 और 2017 की विशेष अपील रिट संख्या 1250 में अपील की।

9. चूंकि सभी विभागीय प्रोन्नतियों (डीपीएस) का प्रतिनिधित्व एकल न्यायाधीश के समक्ष नहीं किया गया था, इसलिए उनमें से कई ने तीसरे पक्ष की अपील को प्राथमिकता दी। खण्ड पीठ ने अपने आक्षेपित फैसले के माध्यम से डीपीएस द्वारा इन अपीलों को यह देखने के बाद स्वीकार कर लिया कि नियम 27, जिस पर एकल न्यायाधीश द्वारा भरोसा किया गया था, में संशोधन किया गया था। खण्ड पीठ ने इस तथ्य ध्यान दें किया कि संशोधन के बाद इसमें संशोधन के परंतुक जोड़े गए हैं।

10. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नियम 27 के मुख्य उपबंध को 10.10.2002 को संशोधित किया गया था जिसमें दूसरा परंतुक जोड़ा

गया था और यह परंतुक तब लागू होगा जब एक ही प्रवर्ग के लिए दो चयन किए जाएंगे। खण्ड पीठ की प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

"हमारी राय में नियम 27 के मुख्य प्रावधान और दूसरे प्रावधान के बीच विरोधाभास है। यदि नियुक्ति के बाद पहले और बाद के चयन को ध्यान में रखते हुए परंतुक लागू किया जाता है, तो किसी दिए गए मामले में, जहां चयन बाद के चयन से पहले शुरू किया गया था, लेकिन बाद के चयन के अनुसार चयनित लोगों को पहले नियुक्ति दी जाती है, नियुक्ति की तिथि की प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। ऐसा पूर्ववर्ती चयन में से उम्मीदवारों की नियुक्ति से पहले अनुवर्ती चयन के अनुसरण में उम्मीदवारों की नियुक्ति के कारण होता है। उन्हें पहले की गई नियुक्ति के बावजूद वरिष्ठता नहीं मिलेगी और इससे नियम 27 में दी गई नियुक्ति की तारीख के महत्व का उल्लंघन होगा। परन्तुक मुख्य उपबंध को अकृत नहीं कर सकता और उन परिस्थितियों में दो उपबंधों पर विचार किया जाना है।यह प्रावधान तब लागू होगा जब दो चयन एक और एक ही श्रेणी के लिए हों।"

11. खंड पीठ के अनुसार इस प्रकार दो श्रेणियां डीपीएस और डीआरएस अलग-अलग थीं और यह डीआरएस के लिए खुला नहीं था, विशेष रूप से लंबे समय के बाद, डीपीएस की वरिष्ठता सूची में नियुक्ति पर सवाल उठाने के लिए। हालांकि, चूंकि डीआरएस/मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने डीपीएस (या उनमें से कुछ) की चयन में भाग लेने के लिए अयोग्यता के

बारे में खंडपीठ के समक्ष तर्क दिया था - (जो 2011 में आयोजित किया गया था) उस मुद्दे को खुला रखा गया था।

पक्षों की दलीलें

12. श्रीमती ऐश्वर्या भाटी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री प्रशांत भूषण ने अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया कि खण्ड पीठ ने इस तथ्य की अनदेखी की कि इस मामले में भर्ती एक ही पद के लिए दो अलग-अलग विज्ञापनों के साथ की गई थी, अपीलकर्ता जो 80% कोटा के खिलाफ खुली श्रेणी से थे, पहले चुने गए थे और विभागीय कर्मचारियों के अन्य समूह को बाद में भर्ती किया गया था।इस संदर्भ में, डीआरएस ने पहले चुने जाने और पहले की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के विवरण का जवाब दिया।दूसरी ओर, डीपीएस ने बाद में जारी किए गए एक अलग विज्ञापन पर प्रतिक्रिया दी और एक अलग चयन प्रक्रिया से गुजरा। सीधे तौर पर, नियम की स्पष्ट शर्तों, यानी नियम 27 के संबंध में, सीधी भर्ती (यानी अपीलकर्ता और उनके जैसे अन्य) की वरिष्ठता डीपीएस से पहले या उससे वरिष्ठ पदों पर निर्धारित की जानी थी, जिन्हें बाद में चुना गया था।

13. यह तर्क दिया गया था कि पहले के नियुक्ति पत्र जारी करने की घटना से डीपीएस को अनुचित और अनुचित लाभ नहीं मिल सकता था क्योंकि इससे सामान्य वरिष्ठता सूची के पहले के स्लॉट से डीआरएस को वंचित किया जा सकता था। इस पहलू पर विस्तार से बताते हुए,

विद्वान अधिवक्ता ने एकल न्यायाधीश की टिप्पणियों पर भरोसा किया और कहा कि डीआर कोटा के लिए चयन या भर्ती का विज्ञापन 25 जनवरी, 2011 को दिया गया था, परीक्षा 17 अप्रैल, 2011 को आयोजित की गई थी और 16 मई, 2011 को डीआर श्रेणी के लिए चयन सूची प्रकाशित की गई थी। हालाँकि, वाणिज्यिक कर विभाग ने जानबूझकर नियुक्ति पत्र जारी करने से रोक दिया और उसी विभाग में काम करने वाले अनुसचिवीय कर्मचारियों के डीपी 20% कोटे को भरने के लिए एक और विज्ञापन जारी किया। डीपी कोटा के लिए विभागीय परीक्षा लगातार दो तारीखों यानी 11.06.2011 और 12.06.2011 को आयोजित की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह इस तथ्य के बावजूद था कि विभागीय परीक्षा मूल रूप से बाद में निर्धारित की गई थी। पहले परीक्षा कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ने के बाद, राज्य असामान्य गति से आगे बढ़ा और डीपी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 20% कोटा के लिए 14.06.2011 को परिणाम प्रकाशित किया और 23.06.2011 को जल्दबाजी में नियुक्ति पत्र जारी किया।इसके बाद ही डीआर श्रेणी के उम्मीदवारों (80 प्रतिशत खुले कोटे के लिए) के नियुक्ति पत्र जारी किए गए।यह प्रस्तुत किया गया था कि इन परिस्थितियों ने स्वयं डीआरएस के खिलाफ द्वेष स्थापित किया और डीपी श्रेणी के उम्मीदवारों को अनावश्यक और अनुचित लाभ देने के लिए राज्य और उसके अधिकारियों की ओर से विज्ञापन।

14. विद्वान अधिवक्ता ने प्रकाश डाला कि विभागीय कर्मचारी संघ के महासचिव द्वारा अभ्यावेदन/पत्र ने वाणिज्यिक कर विभाग पर पहले डीपीएस की भर्ती के लिए दबाव डाला था और दिनांक 19.05.2011 के एक पत्र पर भरोसा किया था।डीपी कोटा के चयन की प्रक्रिया को तेज करने में राज्य का आचरण और कार्रवाई, डीआर भर्तियों के लिए पूर्ण रूप से अलाभकारी है, इस प्रकार अभिलेख से स्थापित किया गया था। विभाग ने वास्तव में 20% विभागीय कोटे के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए अभूतपूर्व प्राथमिकता दी।

15. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि डीआर कोटे के उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने में हुई देरी के लिए राज्य द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण (जो कि पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल चेकअप में लिया गया कुछ समय था) को इन स्थापित तथ्यों के आलोक में देखा जाना चाहिए।विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि 24.06.2011 को डीपी उम्मीदवारों को 20% श्रेणी में नियुक्ति पत्र जारी किए जाने के बाद ही केवल 10 दिन बाद, यानी 14.07.2011 को, डीआर उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे।

16. अंत में यह तर्क दिया गया कि खण्ड पीठ ने मामले के तथ्यों की अनदेखी करते हुए नियमों (राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975 (संक्षेप में, 1975 के नियम) की गलत व्याख्या की। मूल नियम 27 में दिनांक 10.10.2002 की अधिसूचना

द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता की गणना की गई थी। हालांकि, नियम 27 के प्रावधान (2) को बरकरार रखा गया था, जो स्पष्ट रूप से *निर्धारित करता है कि "चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति, जो समीक्षा और संशोधन के अधीन नहीं है, बाद के चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किए गए व्यक्तियों से वरिष्ठ रैंक होगा। वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर और उसी चयन में योग्यता के आधार पर चुने गए व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता अगले नीचे के ग्रेड के समान होगी।"*

17. यह तर्क दिया गया है कि उक्त नियम के परंतुक (2) को बनाए रखने के लिए नियम का आशय उन मामलों में वरिष्ठता की गणना में अस्पष्टता से बचना था, जहां एक ही पद के लिए चयन अर्थात 'कर सहायकों' का चयन दो अलग-अलग स्रोतों द्वारा से किया जाता है, जहां विज्ञापनों और चयन प्रक्रियाओं की तारीख अलग-अलग होती है। परंतुक मुख्य प्रावधान के लिए एक अपवाद बनाता है, और परंतुक का कार्य प्रावधान के मुख्य भाग को सीमित करना है और कुछ ऐसा बनाना है जो परन्तुक के बिना ऑपरेटिव भाग के भीतर होता। इस कोर्ट ने विभिन्न फैसलों, जैसे, *एस. सुंदरम पिल्लई और अन्य बनाम वी. आर. पट्टाभिरामन और अन्य*[6]*; जे. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य कारखानों*

---

6 (1985) 1 एससीसी 591

और बॉयलरों के मुख्य निरीक्षक और अन्य[7], में अभिनिर्धारित किया है कि- *"परन्तुक खंड के मुख्य भाग के लिए एक अपवाद है; लेकिन यह माना जाता है कि आपवादिक मामलों में एक परंतुक स्वयं तथ्यात्मक प्रावधान हो सकता है।"*

18. यह आग्रह किया जाता है कि संशोधित नियम 27 में केवल नियुक्ति की तारीख के आधार पर वरिष्ठता के बारे में बात की गई है, हालांकि, परंतुक (2) वरिष्ठता की गणना के लिए नियम को स्पष्ट करता है जब एक ही पद के लिए दो विज्ञापन हैं, जो उम्मीदवारों की विभिन्न श्रेणियों (स्रोतों) द्वारा से भरे जाते हैं।इसलिए, मुख्य नियम केवल तभी लागू होगा जब भर्ती उसी विज्ञापन द्वारा से होगी। यह उस मामले में लागू नहीं किया जा सकता है जहां पहले विज्ञापन के परिणाम जारी होने के बाद उसी पद के लिए एक और विज्ञापन जारी किया जाता है और बाद के मामले में नियुक्ति आदेश दिया जाता है।मनमानी भर्ती की यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों को उनके पूरे सेवाकाल में उनके वरिष्ठता क्रम से हमेशा वंचित रखेगी जो कि अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

19. डॉ. मनीष सिंघवी, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान राज्य की ओर से और श्री आर. वेंकटरमणि, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तरदाताओं, यानी विभागीय पदोन्नत (डीपी) उम्मीदवारों की ओर से

---

7 (1996) 6 एससीसी 665

उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखा। राज्य प्रतिवादी की ओर से यह दलील दी गई कि 531 पदों के सृजन के लिए अनुमति 01.09.2009 को दी गई थी और बाद में 23 पद जोड़े गए थे। 2011 में जारी किए गए दो विज्ञापनों (एक डीआरएस के 80% कोटे के लिए और दूसरा डीपीएस के 20% कोटे को भरने के लिए) के माध्यम से की गई प्रश्नगत भर्ती इन नए सृजित पदों को भरने के लिए पहला भर्ती अभियान था जो अब तक अस्तित्व में नहीं थे। राज्य की ओर से आग्रह किया गया कि मामले की इन परिस्थितियों को एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से ध्यान में रखा जाना है यानी बड़ी संख्या में पदों को भरने का राज्य का यह पहला प्रयास है, जब वे संवर्गीकृत हो गए थे और लगभग दो वर्षों से खाली पड़े थे।विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नि:संदेह डीआर रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन समय से पहले अर्थात जनवरी 201 में जारी किए गए थे। हालांकि इस विज्ञापन के जवाब में 80% रिक्तियों (अर्थात् 443 रिक्तियों) के लिए कम से कम 15,352 आवेदन प्राप्त हुए थे; उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए इनकी जांच की जानी है; उसके बाद लिखित परीक्षा 17.04.2011 को आयोजित की गई थी।356 उम्मीदवारों के लिए 15.05.2011 को टंकण परीक्षा भी आयोजित किया गया था।16.05.2011 को एक अनंतिम परिणाम घोषित किया गया था।विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के लिए पुलिस सत्यापन

और चिकित्सा जांच प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा और अंततः 01.07.2011 को पूरा किया गया।

20. यह आग्रह किया गया कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो महीने की अवधि को किसी भी तरह से अनुचित नहीं माना जा सकता है- क्योंकि राजस्थान भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा राज्य है और यहां लगभग 35 जिले हैं।इस दौरान विभागीय उम्मीदवारों के लिए विज्ञापन 24.05.2011 को जारी किया गया था।111 रिक्तियों को भरने के लिए 232 आवेदन प्राप्त हुए, लिखित परीक्षा दो तिथियों अर्थात 11 और 12 जून, 2011 को आयोजित की गई।डीपीएस को किसी टाइपिंग टेस्ट से गुजरने की आवश्यकता नहीं थी और न ही पुलिस सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता थी क्योंकि वे काफी समय से सरकार के साथ काम कर रहे थे। इस प्रकार अंतिम नियुक्ति की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान थी।इन परिस्थितियों में उनके परिणाम संकलित किए गए और 14 जून, 2011 को प्रकाशित किए गए, लेकिन चयन प्रक्रिया की सरलीकृत और संक्षिप्त प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उन्हें 24 जून, 2011 को नियुक्त किया गया।

21. विद्वान अपर महाधिवक्ता एवं उत्तरदाताओं के वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि डिवीजन बेंच ने सही निष्कर्ष निकाला है कि नियम 27 के पीछे अंतर्निहित विचार और इसके द्वारा इंगित वरिष्ठता का सिद्धांत जो कि है पहले चुने गए लोग बाद में चुने गए लोगों से पहले रैंक प्राप्त

करेंगे, उसी श्रेणी में भर्ती होने के मामले में लागू होंगे।इस प्रकार, उदाहरण के लिए, यदि डीआर कोटा के भीतर चयन के दो सेट हैं, तो नियम 27 में उल्लिखित नियम पूरी तरह से लागू होता है, हालांकि यह सिद्धांत वहां लागू नहीं होगा जहां भर्ती किए गए लोगों को विभिन्न श्रेणियों जैसे पदोन्नत और सीधी भर्ती से नियुक्त किया जाता है।ऐसे मामलों में नियम का मुख्य भाग अर्थात संवर्ग में प्रवेश के आधार पर वरिष्ठता पूरी तरह से लागू होगी।

22. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई निर्णयों में इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण अपने प्रचालन के क्षेत्र में परंतुक को सीमित करने का रहा है और इसे उस प्रावधान में निहित मुख्य या अधिनियमित भाग को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं देता है जिससे यह परन्तुक संबंधित है। इस प्रकार यह आग्रह किया जाता है कि परंतुक की व्याख्या अधिनियमन को रद्द करने या मुख्य खंड या प्रावधान द्वारा प्रदत्त किसी चीज को वापस लेने के रूप में नहीं की जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता ने इस संबंध में कतिपय निर्णयों पर भरोसा किया[8]। विद्वान एएजी ने इस बात पर जोर दिया कि अभिलेख पर मौजूद तथ्यों से पता चलता है कि संपूर्ण संवर्ग पहली बार एकल अधिसूचना दिनांक 01.12.2010 द्वारा बनाया गया था।दोनों

---

8 कैसियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा राज्य (2016) 6 एससीसी 209 और रोहिताश कुमार बनाम ओम प्रकाश शर्मा और अन्य (2013) 11 एससीसी 451।

श्रेणियों में भर्ती पहली बार की गई।विज्ञापन अलग-अलग तारीखों पर जारी किए गए थे - एक सीधी भर्ती (डीआरएस) के लिए और दूसरा सीधे पदोन्नत (डीपीएस) के लिए, इन्हे अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया नहीं बनाया गया।वे इसमें समसामयिक थे कि राज्य का इरादा चयनित उम्मीदवारों को एक ही पद पर नियुक्त करना था। इस प्रकार, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि डीआर उम्मीदवारों के लिए 80% कोटा में की गई नियुक्तियां पिछले वर्ष के लिए थीं (भर्ती नियमों[9] के तहत "वर्ष" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए)।

23. इस संबंध में यह रेखांकित किया गया था कि भर्ती और चयन प्रक्रिया के आयोजन का निर्णय एक समग्र था - हालांकि विज्ञापन अलग-अलग तारीखों पर जारी किए गए थे।यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया एक संयुक्त प्रक्रिया थी।यह देखते हुए कि डीआरएस के लिए निर्धारित 80% कोटा विभिन्न पात्रता मानदंडों के साथ उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध था, आवश्यकता होने पर, एक अलग विज्ञापन जारी किया गया था।इसी

---

9 नियम 2 इस प्रकार हैः

"**परिभाषा** - 2. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

(क).....

(ख).....

xxxxxx *xxxxxx* *xxxxxx*

(ठ) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।"

तरह, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 20% विभागीय पदोन्नति कोटा केवल वाणिज्यिक कर विभाग के भीतर काम करने वालों द्वारा भरा जा सकता है (और जो डीआरएस द्वारा नहीं भरा जा सकता है), प्रासंगिक पात्रता शर्तों के साथ एक अलग प्रकार का विज्ञापन जारी किया गया था।इसका मतलब यह नहीं था कि अलग-अलग चयन प्रक्रियाएं आयोजित की गईं; चूंकि विभाग में पहली बार एक नए पद पर रिक्तियां थीं, इसलिए भर्ती को सामान्य माना जाना था।

<u>प्रासंगिक नियमः</u>

24. राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवाएं (सामान्य शाखा) नियम, 1975 के नियम 27 पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ध्यान दिया गया। इस नियम का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया हैः

“27. वरिष्ठता "सेवा के निम्नतम पद पर नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता या सेवा के प्रत्येक समूह/अनुभागों में निम्नतम श्रेणियों के पद की वरिष्ठता, जैसा भी मामला हो, तारीख से निर्धारित किया जाएगा लेकिन सेवा में अन्य उच्च पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में या सेवा में प्रत्येक समूह/अनुभाग में पदों की अन्य उच्च श्रेणी, जैसा भी मामला हो, ऐसे पदों पर उनके नियमित चयन की तिथि से निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते

(1) नियमों के प्रारंभ से पहले सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, और/या राजस्थान के राज्यों के पूर्व-पुनर्गठन की सेवाओं के एकीकरण की प्रक्रिया में या राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित नए राजस्थान राज्य की सेवाएं, तदर्थ आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित, संशोधित या परिवर्तित की जाएंगी;

(2) कि एक चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किए गए व्यक्ति, जो समीक्षा और संशोधन के अधीन नहीं हैं, उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे जो बाद के चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किए गए हैं।वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर और उसी चयन में योग्यता के आधार पर चुने गए व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता वही होगी जो अगले नीचे के ग्रेड में है;"

25. 10.10.2002 से प्रभावी, नियम 27 के मुख्य उपबंध को इसके नीचे के दो परन्तुकों को बनाए रखते हुए भी संशोधित किया गया था।खंडपीठ ने अपने आक्षेपित फैसले में इसका उल्लेख किया था। नियम में संशोधन का उद्धरण नीचे दिया गया हैः

"संशोधन: इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम में, तथ्यात्मक प्रावधानों (उनके प्रावधानों को छोड़कर) के संबंध में प्रत्येक सेवा नियम कॉलम संख्या 4 के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसका अर्थ है:-

'सेवा संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में वरिष्ठता इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी और उनकी नियुक्ति की तारीख से तय की जाएगी। जिन्हें तदर्थ या अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया है, उनके नियमित चयन के बाद उन पर विचार नहीं किया जाएगा।"

26. उपर्युक्त मुख्य उपबंध (अर्थात् नियम 27 [1]) के निम्नलिखित परंतुक अक्षुण्ण रहेः

"बशर्ते कि -

(1) यह कि नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता और/अथवा राजस्थान राज्यों के पूर्व -पुनर्गठन की सेवाओं के एकीकरण की प्रक्रिया में या राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित नए राजस्थान राज्य की सेवाएं, तदर्थ आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित, संशोधित या परिवर्तित की जाएंगी;

(2) चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किए गए व्यक्ति, जो समीक्षा और संशोधन के अधीन नहीं है, बाद में चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किए गए व्यक्तियों से वरिष्ठ रैंक पर होंगे।वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर और उसी चयन में योग्यता के आधार पर चुने गए व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता वही होगी जो अगले नीचे के ग्रेड में है;

27. इस प्रकार, मुख्य प्रावधान में संशोधन किया गया ताकि स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया जा सके कि संवर्ग में वरिष्ठता संवर्ग के कर्मचारियों, या अधिकारियों की नियुक्ति की तारीख से तय की जाएगी।

28. यहां तय किया जाने वाला प्रश्न इस तथ्य के संबंध में है कि डीपी को डीआर से पहले नियुक्त किया गया था, जहां बाद में, जैसा कि उनके द्वारा तर्क दिया गया है, "*उसी चयन में*"[10] योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया है। डीआरएस का तर्क है कि डीपीएस के बाद उनकी नियुक्ति विभाग (या बल्कि विभाग के कुछ अधिकारियों) द्वारा हेरफेर का परिणाम है, जो डीपीएस का पक्ष लेना चाहते थे; और यह कि चूंकि उनका चयन डीपीएस से पहले शुरू हुआ था, इसलिए पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के लिए दूसरा परंतुक लागू होता है।वे यह भी तर्क देते हैं कि चयन- नियमों के संदर्भ में, "*बाद में चयन*" आवश्यक रूप से कालानुक्रमिक रूप से बाद की घटना को संदर्भित करता है; वर्तमान मामले में, डीआरएस की भर्ती जनवरी, 2011 में विज्ञापन के साथ शुरू हुई (और इस प्रकार, नियम 2 (1) के संबंध में, प्रारम्भिक वित्तीय वर्ष में) जबकि डीपीएस के लिए चयन प्रक्रिया मई, 2011 में शुरू हुई थी।

29. पूरे नियम (नियम 27 [1] और दो परन्तुकों) के साधारण पठन पर यह स्पष्ट है कि (क) 2002 के संशोधन से पहले, किसी भी विभाग में "*निम्नतम श्रेणियों के पदों*" पर नियुक्त कर्मियों की वरिष्ठता नियुक्ति

---

10 नियम 27 (1) का दूसरा परंतुक

की तारीख से निर्धारित की जानी थी; हालाँकि, प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए, यह चयन की तिथि से होना था; (ख) *2002 के संशोधन के बाद*, वरिष्ठता (नियम 27 (1) के कारण) पद या सेवा में नियुक्ति की तारीख को तय की जानी है; (ग) हालांकि, राज्य के पूर्व-राज्य एकीकरण (राजस्थान) या सेवाओं के पूर्व-एकीकरण के मामले में, वरिष्ठता को "*तदर्थ आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है*" - इसका स्पष्ट रूप से मतलब था एक "सावधि विधि" खंड, यानी सीमित अवधि के लिए प्रचालक; (घ) दूसरा परंतुक, - जो डीआरएस द्वारा सेवा में डाला गया है, कहता है कि पहले चुने गए लोगों की वरिष्ठता बाद में चुने गए लोगों पर निर्धारित की जाएगी।

30. स्पष्ट रूप से, नियम का प्रमुख आदेश यह है कि वरिष्ठता *नियुक्ति की तिथि* के आधार पर निर्धारित की जाती है ("*उनकी नियुक्ति की तिथि से तय की जाएगी*")। परन्तुक (2) में दो नियम सूचीबद्ध हैं। पहला यह है कि पूर्व चयन के माध्यम से चुने गए और नियुक्त किए गए बाद की चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित और नियुक्त किए गए लोगों से वरिष्ठ होंगे। इस मामले में, उच्च न्यायालय की राय थी कि यह नियम (अर्थात परंतुक) *एक ही स्रोत से* चयन पर लागू होता है, यानी जहां सीधी भर्ती के दो सेट नियुक्त किए गए थे, जो पिछली भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए थे, वे उन लोगों से वरिष्ठ होंगे जिन्हें बाद में भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किया गया था।यह

व्याख्या, इस न्यायालय की राय में, हितकारी है। भर्ती के एक बैच की अंतिम नियुक्ति में देरी के कई कारण हो सकते हैं:भर्ती प्रक्रिया के कुछ भाग में चुनौतियाँ (जैसे चयनीत सूची, साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाना आदि), जिस अवधि के दौरान, उत्तरवर्ती भर्ती की जा सकती है।किसी भी आशंका को दूर करने के लिए कि नियुक्तियों में से कौन वरिष्ठ होगा, और यदि पहले की प्रक्रिया वालों को बाद में नियुक्त किया जाता हैं, तो परंतुक स्पष्ट करता है कि पहले की प्रक्रिया से उम्मीदवार वरिष्ठ होंगे, मुख्य नियम में नियुक्ति की तारीख आधारित वरिष्ठता की बात करने के बावजूद। यही तर्क विभागीय प्रोन्नतियों पर भी लागू होगा, यदि चयन के माध्यम से प्रोन्नतियों के दो बैच नियुक्त किए जाते हैं। दूसरे परंतुक का दूसरा अंग स्पष्ट करता है जब योग्यता आधारित, या वरिष्ठता आधारित पदोन्नति का सहारा लिया जाता है, तो फीडर संवर्ग में लागू मानदंड वरिष्ठता होगा, योग्यता के नियम (चयन में) के मार्गदर्शक सिद्धांत होने के बारे में किसी भी बहस को रोकने के लिए।

31. *प्रेम कुमार वर्मा बनाम भारत संघ*[11] वाले मामले में इस न्यायालय को रेलवे स्थापना नियमावली के नियम 303 पर विचार करना पड़ा, जिसे वर्तमान मामले में नियम 27 की तरह अभिव्यक्त किया गया था। प्रासंगिक चर्चा का सार इस प्रकार हैः

---

11 (1998) 5 एससीसी 457

"4. बार में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के मद्देनजर पहला प्रश्न जो विचार के लिए उठेगा वह यह है कि कौन सा नियम परस्पर वरिष्ठता को नियंत्रित करेगा।यह निर्विवाद है कि रिक्तियां जुलाई 1989 से पहले उत्पन्न हुई थीं और उक्त पद के लिए विज्ञापन जुलाई 1989 तक जारी किया गया था और अंत में रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी चयन प्रक्रिया पूरी की और 11-7-1989 को 29 उम्मीदवारों का चयन किया। इसलिए, प्रासंगिक नियम, जो उस समय मौजूद थे, पारस्परिक वरिष्ठता को नियंत्रित करेंगे।विचार के लिए अगला प्रश्न यह उठता है कि कौन सा प्रासंगिक नियम है जो जुलाई 1989 में लागू था।हमारे समक्ष प्रस्तुत सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि नियमावली का पैरा 303, जैसा कि वह जुलाई 1989 में था, निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

"303. रेलवे सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जानी चाहिए:

(क) जिन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण स्कूलों में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, उन्हें कार्यकारी पदों पर नियुक्ति से पहले प्रशिक्षण अवधि के अंत में आयोजित परीक्षा में प्राप्त योग्यता के क्रम में संबंधित ग्रेड में वरिष्ठता क्रम में रखा जाएगा।

(ख) जिन उम्मीदवारों को किसी प्रशिक्षण से गुजरना नहीं है, वरिष्ठता रेलवे सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट योग्यता क्रम के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।"

बाद में वर्ष 1990 में किसी समय नियम 303 (क) में निम्नलिखित अभिव्यक्ति अंतःस्थापित करके संशोधन किया गयाः

"जो किसी भी कारण से बाद के क्रम में शामिल हो गए और जिन्होंने बाद के मौके में परीक्षा उत्तीर्ण की, वे उन लोगों से कनिष्ठ रैंक करेंगे जिन्होंने पहले क्रम में परीक्षा उत्तीर्ण की थी।"

उपर्युक्त नियम को 1993 में आगे संशोधित किया गया जो इस प्रकार हैः

"हालांकि, एक ही आरआरबी पैनल से संबंधित व्यक्तियों को प्रशासनिक कारणों से बैचों में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, न कि उम्मीदवारों के लिए जिम्मेदार कारणों के कारण, पारस्परिक वरिष्ठता को बैचवार विनियमित किया जाएगा, बशर्ते आरआरबी के पैनल में ऊपर के व्यक्तियों को प्रशासनिक कारणों से प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त बैच (वरिष्ठता के अनुसार) में नहीं भेजा जाएगा उन्हें उम्मीदवारों के साथ जोड़ा जाएगा जिन्होंने पारस्परिक वरिष्ठता को नियमित करने के उद्देश्य से उपयुक्त बैच में प्रशिक्षण लिया है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण कर लें।"

5. हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि पद जुलाई, 1989 से पूर्व रिक्त थे और चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी और भर्ती बोर्ड ने 11-7-1989 को उम्मीदवारों का चयन किया था, 5-5-1990 को पेश किए गए संशोधन और 1993 के आगे के संशोधन का कोई आवेदन नहीं होगा और यह असंशोधित नियम 303 (क) है, जैसा कि यह 11-7-1989 को था, जो परस्पर वरिष्ठता के मामले को नियंत्रित करेगा। पैरा 303 के प्रावधानों का विश्लेषण बताता है कि जहां उम्मीदवारों को रेलवे सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा से चयन किए जाने के बाद कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, वहां उनकी वरिष्ठता का निर्धारण प्रशिक्षण अवधि के अंत में आयोजित परीक्षा में उनकी संबंधित योग्यता के आधार पर किया जाता है और जहां उम्मीदवारों को कोई प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता है, वहां वरिष्ठता का निर्धारण रेलवे सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर किया जाता है। वर्तमान मामले में, उम्मीदवारों को प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा था और वास्तव में उन्होंने बैचों में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है।इस मामले में उनकी वरिष्ठता का निर्धारण प्रशिक्षण अवधि के अंत में आयोजित परीक्षा में प्राप्त उनकी योग्यता के आधार पर रेलवे प्राधिकारी द्वारा किया गया था। अधिकरण ने उक्त वरिष्ठता को एक नियम के आधार

पर बदल कर गलती की, जो रिक्ति होने की तारीख और चयन पूरा होने की तारीख पर अस्तित्व में नहीं था।"

32. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विज्ञापन (पूरे संवर्ग को भरने के लिए, दोनों कोटा या भर्ती के वर्गों में) एक के बाद एक जारी किए गए थे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नव सृजित संवर्ग के लिए पहला चयन और भर्ती थी, विलम्ब जो प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण हुआ हो (और साथ ही प्रक्रिया पूरी होने के कारण, जैसे कि पूर्ववृत्त का सत्यापन) प्रोन्नत व्यक्तियों को उनकी नियुक्ति की तारीखों के आधार पर दी गई वरिष्ठता, इस मामले में नियम 27 द्वारा न्यायोचित है। इस न्यायालय की राय में, आक्षेपित निर्णय गलत नहीं है, यह हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

33. उपरोक्त विवेचना को ध्यान में रखते हुए, खर्चों पर आदेश के बिना अपीलें खारिज की जाती हैं।

न्यायाधीश [इंदिरा बनर्जी]

न्यायाधीश [एस. रविन्द्र भट्ट]

नई दिल्ली, 26 नवंबर, 2020

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।)

अस्वीकरण : यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है

और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।